SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

भारतीय राजनीति में वैश्वीकरण का प्रभावः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

सरोज कुमार, पी–एचडी, राजनीति विज्ञान
पार्वती साइंस कॉलेज, बी. एन. मण्डल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
सरोज कुमार, पी–एचडी
E-mail : sarojkumara1982@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 09/10/2025
Revised on : 11/12/2025
Accepted on : 20/12/2025
Overall Similarity : 00% on 12/12/2025

शोध सार

यह शोध–पत्र वैश्वीकरण के भारतीय राजनीति पर पड़े व्यापक, संरचनात्मक और बहुपरत प्रभावों का संक्षिप्त किंतु सारगर्भित विश्लेषण प्रस्तुत करता है। 1991 के उदारीकरण के बाद भारत में वैश्वीकरण ने राजनीतिक निर्णय–प्रक्रिया, शासन–प्रशासन, चुनावी रणनीतियों, दलों के घोषणापत्र, मीडिया–माध्यमों तथा डिजिटल राजनीति को उल्लेखनीय रूप से रूपांतरित किया। अध्ययन उद्घाटित करता है कि वैश्विक आर्थिक प्रवाह, तकनीकी नवाचार और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ, जैसे WTO, IMF और विश्व बैंक भारतीय नीतिगत रुझानों और आर्थिक प्राथमिकताओं को प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रही हैं। सैद्धांतिक रूप से उदारवादी वैश्वीकरण दृष्टिकोण, मार्क्सवादी आलोचना, वॉलरस्टीन के विश्व–प्रणाली सिद्धांत और राष्ट्र–राज्य के परिवर्तन सिद्धांत का उपयोग करते हुए शोध यह स्पष्ट करता है कि वैश्वीकरण ने एक ओर प्रतिस्पर्धा, निवेश, डिजिटल सुशासन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के नए अवसर खोले हैं, वहीं दूसरी ओर असमानता, कॉर्पोरेट वर्चस्व, बाहरी दबाव और सांस्कृतिक चुनौतियों को भी गहराया है। राज्य की भूमिका नियंत्रक से समन्वयक में रूपांतरित होती दिखाई देती है। अतः निष्कर्षतः वैश्वीकरण भारतीय राजनीति के लिए न पूर्णतः वरदान है, न अभिशाप; बल्कि अवसरों और चुनौतियों से युक्त एक गतिशील, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है, जिसकी दिशा भारत की लोकतांत्रिक क्षमता और नीतिगत संतुलन पर निर्भर करेगी।

मुख्य शब्द

वैश्वीकरण, भारतीय राजनीति, लोकतंत्र, चुनाव आयोग, सुशासन.

परिचय

वैश्वीकरण 21वीं सदी की सबसे निर्णायक ऐतिहासिक प्रक्रियाओं में से एक है, जिसने विश्व की आर्थिक संरचनाओं, सामाजिक संबंधों और राजनीतिक व्यवस्थाओं को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है। आज किसी भी राष्ट्र की राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति या शासन–पद्धति को समझना वैश्वीकरण से अलग करके संभव नहीं है। यह केवल आर्थिक परिघटना नहीं, बल्कि वह व्यापक सामाजिक–राजनीतिक परिवर्तन है जिसने राज्यों की संप्रभुता, नीति–निर्माण की दिशा, प्रशासनिक व्यवस्था और नागरिक समाज की भूमिका को नए सिरे से आकार दिया है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण लोकतांत्रिक देश में इसका प्रभाव विशेष रूप से बहुआयामी और जटिल रूप में प्रकट होता है। भारतीय राजनीति सदैव परिवर्तनशील रही है कभी औपनिवेशिक शासन के प्रभाव से, कभी अंतरराष्ट्रीय वैचारिक परिस्थितियों से और कभी आंतरिक सामाजिक संरचना से संचालित परंतु 1990 के दशक के बाद वैश्वीकरण ने भारतीय राजनीति को एक नए मोड़ पर पहुँचा दिया। आर्थिक संकट, राजकोषीय दबाव और विदेशी मुद्रा संकट ने यह स्पष्ट कर दिया कि पारंपरिक आर्थिक ढांचे और नीति–निर्माण की दिशा को बदलना अनिवार्य हो गया है। इसी पृष्ठभूमि में 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) की नीतियों की शुरुआत हुई, जिसने भारत के राजनीतिक–आर्थिक परिप्रेक्ष्य को मूलभूत रूप से परिवर्तित किया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था, नियोजित विकास और सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार को आधार बनाया था, ताकि आर्थिक समानता और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके किंतु 1991 के पश्चात यह मॉडल बाजार–उन्मुख वैश्विक ढांचे के साथ समायोजित होने लगा। इस परिवर्तन ने राज्य की पारंपरिक भूमिका को नियंत्रक और संरक्षक से बदलकर समन्वयक तथा प्रवर्तक में परिवर्तित कर दिया। सरकार की आर्थिक गतिविधियों में सहभागिता घटने लगी और निजी क्षेत्र, बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा विदेशी निवेश का प्रभाव बढ़ने लगा। वैश्वीकरण के प्रभाव से भारतीय राजनीति के विभिन्न पक्ष प्रभावित हुए। राजनीतिक दलों ने अपनी नीतियों, घोषणापत्रों और चुनावी रणनीतियों को बदलते वैश्विक आर्थिक–सामाजिक वातावरण के अनुरूप ढालना शुरू किया। चुनावी राजनीति में पूँजी का महत्व बढ़ा, कॉर्पोरेट फंडिंग एक प्रमुख तत्व बनकर उभरी, और डिजिटल मीडिया विशेषकर इंटरनेट, सोशल मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने राजनीतिक संचार, प्रचार और जनमत–निर्माण की प्रक्रिया को पूरी तरह बदल दिया।

वैश्विक संस्थाएँ जैसे IMF, विश्व बैंक और WTO भारतीय नीति–निर्माण पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालने लगीं। व्यापार उदारीकरण, विनिवेश, विदेशी निवेश नीति और वित्तीय सुधार जैसे निर्णय अब केवल घरेलू राजनीतिक आवश्यकताओं से नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक परिवेश और अंतरराष्ट्रीय मानकों से भी प्रभावित होने लगे। भारत की विदेश नीति पर भी वैश्वीकरण का गहरा प्रभाव देखा गया। गुटनिरपेक्षता के पारंपरिक दृष्टिकोण में लचीलापन आया और भारत ने बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था में सामरिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को प्राथमिकता दी। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका अधिक सक्रिय हुई और वैश्विक मुद्दों जैसे – व्यापार, पर्यावरण और सुरक्षा पर सहमति तथा सहयोग महत्वपूर्ण बन गए।

समग्रतः, वैश्वीकरण ने भारतीय राजनीति में नई दिशाएँ, नई चुनौतियाँ और नए अवसर प्रदान किए। जहाँ इसने विकास, तकनीकी प्रगति और वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा दिया, वहीं संप्रभुता, असमानता और सांस्कृतिक पहचान जैसे प्रश्नों को भी जटिल बनाया। इसी द्वंद्वात्मक स्वरूप के कारण वैश्वीकरण और भारतीय राजनीति का संबंध सतत् परिवर्तनशील और गहन अध्ययन योग्य बन जाता है।

साहित्य समीक्षा

एंथनी गिड्डन्स (1990) ने अपनी पुस्तक The Consequences of Modernity में आधुनिकता और वैश्वीकरण के संबंध को अत्यंत गहराई से समझाया है। उनके अनुसार वैश्वीकरण केवल आर्थिक घटनाक्रम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संरचनाओं का व्यापक परिवर्तन है। गिड्डन्स यह बताते हैं कि आधुनिकता के कारण समय और स्थान की सीमाएँ टूटने लगीं, जिससे राजनीतिक निर्णय भी वैश्विक कारकों पर निर्भर होने लगे।

जगदीश भगवती (2004) की पुस्तक In Defines of Globalization में वैश्वीकरण के समर्थक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। लेखक का तर्क है कि वैश्वीकरण विकासशील देशों में आर्थिक अवसरों, रोजगार और व्यापारिक स्वतंत्रता को बढ़ाता है। वह यह भी बताते हैं कि वैश्विक बाज़ार लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाते हैं। भारतीय राजनीति के संदर्भ में भगवती की यह व्याख्या महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्पष्ट करती है कि उदारीकरण के बाद नीति–निर्माण में आर्थिक तर्कों, खुली प्रतिस्पर्धा और विदेशी निवेश की भूमिका क्यों बढ़ी।

अमरत्य सेन (1999) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक Development as Freedom में विकास को मात्र आर्थिक वृद्धि नहीं, बल्कि मानव स्वतंत्रता का विस्तार मानते हैं। उनका तर्क है कि वैश्वीकरण से प्राप्त आर्थिक लाभ तभी सार्थक हैं जब वे मानव क्षमताओं, सामाजिक समानता और राजनीतिक स्वतंत्रता को बढ़ाते हैं। यह पुस्तक भारतीय राजनीति में वैश्वीकरण के सामाजिक एवं मानवीय प्रभावों को समझने का एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है।

मैनुअल कॅस्टेल्स (1996) ने पुस्तक The Rise of the Network Society में सूचना–प्रौद्योगिकी आधारित वैश्विक नेटवर्क समाज के उदय का विश्लेषण किया है। वह बताते हैं कि आधुनिक राजनीति अब मुख्यतः सूचना, डिजिटल संचार और वैश्विक नेटवर्क पर आधारित हो गई है। यह दृष्टिकोण भारतीय राजनीति को समझने में अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि 21वीं सदी में सोशल मीडिया, डिजिटल अभियान और सूचना–आधारित चुनावी रणनीतियों ने राजनीति की प्रकृति को पूरी तरह बदल दिया है। कॅस्टेल्स का तर्क है कि राजनीतिक शक्ति अब उन लोगों के पास है जो वैश्विक संचार के नेटवर्क को नियंत्रित करते हैं।

समीर अमीन (1997) ने अपनी कृति Capitalism in the Age of Globalization में वैश्वीकरण की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं और इसे पूँजीवादी शक्तियों का विस्तार बताते हैं। उनके अनुसार वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो विकसित देशों को लाभ पहुंचाती है, जबकि विकासशील देश आर्थिक निर्भरता और राजनीतिक नियंत्रण के जोखिम में फँस जाते हैं।

शोध के उद्देश्य

1. भारतीय राजनीति पर वैश्वीकरण के बहुआयामी प्रभावों का विश्लेषण करना, विशेष रूप से राजनीतिक दलों, नीति–निर्माण प्रक्रिया, चुनावी रणनीतियों और शासन व्यवस्था पर इसके परिणामों का मूल्यांकन करना।
2. वैश्वीकरण के आगमन के बाद भारत में राज्य की भूमिका, संप्रभुता और लोकतांत्रिक संस्थाओं में आए परिवर्तनों का अध्ययन करना, तथा इन परिवर्तनों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं की पहचान करना।

शोध प्रश्न

1. वैश्वीकरण ने भारतीय राजनीति की संरचना, कार्यप्रणाली और नीति–निर्माण प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित किया है?
2. क्या वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं और राजनीतिक संस्कृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं? यदि हाँ, तो वे परिवर्तन किस दिशा में हैं?

शोध–परिकल्पना

1. वैश्वीकरण ने भारतीय राजनीति की नीति–निर्माण प्रक्रिया को अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं और वैश्विक बाजार की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील और अनुकूल बना दिया है।
2. वैश्वीकरण के प्रभाव से भारतीय लोकतांत्रिक संस्थाओं और राजनीतिक संस्कृति में संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं, जिनमें तकनीक–आधारित राजनीतिक संचार, कॉर्पोरेट प्रभाव और चुनावी प्रतिस्पर्धा में वृद्धि प्रमुख तत्व हैं।

शोध–पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक (Descriptive) तथा विश्लेषणात्मक (Analytical) दोनों प्रकार का है। वर्णनात्मक

शोध के माध्यम से वैश्वीकरण, भारतीय राजनीति, नीतिगत परिवर्तनों और ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है।

आंकड़ो का संग्रह

द्वितीयक समंकः प्रस्तुत शोध–पत्र मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। इनमें विभिन्न पुस्तकें, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय जर्नल, सरकारी रिपोर्टें (जैसे संसद रिपोर्ट, नीति आयोग दस्तावेज़) अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्टें, चुनाव आयोग के दस्तावेज़ इत्यादि शामिल हैं।

सैद्धांतिक रूपरेखा

भारतीय राजनीति पर वैश्वीकरण के प्रभाव को समझने के लिए आवश्यक है कि अध्ययन एक ठोस और बहुआयामी सैद्धांतिक आधार पर आधारित हो। वैश्वीकरण स्वभावतः आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीकी स्तरों पर परिवर्तनकारी प्रक्रिया है; अतः इसके विश्लेषण के लिए एकल सिद्धांत पर्याप्त नहीं होता। इस अध्ययन में तीन प्रमुख सैद्धांतिक दृष्टिकोणों उदारवादी वैश्वीकरण सिद्धांत, मार्क्सवादी वैश्वीकरण आलोचना, वॉलरस्टीन का विश्व–प्रणाली सिद्धांत को आधार बनाया गया है। ये सिद्धांत भारतीय राजनीति में नीतिगत बदलावों, वैश्विक दबावों तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में उभरते परिवर्तनों का व्यापक व्याख्यान प्रदान करते हैं।

उदारवादी वैश्वीकरण सिद्धांत

उदारवादी दृष्टिकोण वैश्वीकरण को आर्थिक उदारीकरण, मुक्त व्यापार, प्रतिस्पर्धा और पूँजी के प्रवाह को बढ़ाने वाली शक्ति के रूप में देखता है। इस सिद्धांत के अनुसार वैश्वीकरण राष्ट्रों के बीच सहयोग, पारदर्शिता और सुशासन को प्रोत्साहित करता है। भारत में 1991 के आर्थिक सुधार उदारवादी वैश्वीकरण की स्पष्ट अभिव्यक्ति हैं, जिनके बाद नीति–निर्माण, राजनीतिक प्राथमिकताएँ और चुनावी रणनीतियाँ बाजार–उन्मुख हो गईं। IMF, विश्व बैंक और WTO जैसी संस्थाएँ भारतीय आर्थिक नीतियों को आधुनिक, प्रतिस्पर्धी और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। इस दृष्टिकोण से वैश्वीकरण भारतीय राजनीति में आधुनिकीकरण, डिजिटलाइजेशन और निवेश वृद्धि का कारक माना जाता है।

मार्क्सवादी वैश्वीकरण आलोचना

मार्क्सवादी दृष्टि में वैश्वीकरण पूँजीवादी विस्तार का नया स्वरूप है, जिसका मूल उद्देश्य विकसित देशों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों की रक्षा करना है। यह सिद्धांत मानता है कि वैश्वीकरण विकासशील देशों में असमानता बढ़ाता है और नीति–निर्माण को पूँजी–हितों के अधीन कर देता है। भारत में उदारीकरण के बाद श्रम अधिकारों में ढील, असंगठित क्षेत्र की असुरक्षा, भूमि अधिग्रहण तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बढ़ता प्रभाव इस आलोचना की पुष्टि करते हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार भारतीय राजनीति में कॉर्पोरेट फंडिंग और निजी हितों का हस्तक्षेप बढ़ा है, जिससे नीति–निर्माण की लोकतांत्रिक प्रकृति कमजोर पड़ सकती है।

वॉलरस्टीन का विश्व–प्रणाली सिद्धांत

वॉलरस्टीन वैश्विक अर्थव्यवस्था को कोर, अर्ध–परिधि और परिधि देशों में विभाजित करते हैं। भारत अर्ध–परिधि की श्रेणी में आता है यानी वह वैश्विक प्रतिस्पर्धा में शामिल है, पर कई क्षेत्रों में विकसित देशों पर निर्भर भी है। यह सिद्धांत भारत की व्यापार नीतियों, पेटेंट कानूनों, कृषि सब्सिडी, पर्यावरण नियमों और विदेशी निवेश नीतियों पर वैश्विक दबावों की व्याख्या करता है। इससे स्पष्ट होता है कि वैश्वीकरण भारत को अवसर तो देता है, पर उसके साथ संरचनात्मक निर्भरता और शक्तिगत असंतुलन भी उत्पन्न करता है।

इन तीनों सिद्धांतों का समग्र विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि वैश्वीकरण भारतीय राजनीति में अवसरों और चुनौतियों दोनों को जन्म देने वाली बहुस्तरीय प्रक्रिया है, जिसका प्रभाव संरचनात्मक, विचारधारात्मक और संस्थागत स्तरों पर व्यापक रूप से दिखाई देता है।

भारतीय राजनीति में वैश्वीकरण का प्रभावः समग्र विश्लेषण

भारत का लोकतंत्र विश्व के सबसे विविध, जटिल और सहभागितापूर्ण राजनीतिक ढाँचों में से एक है। यह केवल संवैधानिक प्रावधानों पर आधारित नहीं, बल्कि बहुजातीय, बहुभाषी और बहुधार्मिक सामाजिक संरचना का प्रतिबिंब भी है। ऐसे में वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने पिछले तीन दशकों में भारतीय लोकतंत्र की नीतियों, संस्थाओं, चुनावी व्यवहार, नागरिक सहभागिता और सांस्कृतिक राजनीति को गहराई से प्रभावित किया है। आर्थिक उदारीकरण, तकनीकी क्रांति, अंतरराष्ट्रीय संस्थागत दबाव, डिजिटल मीडिया और वैश्विक राजनीतिक विमर्शों ने मिलकर लोकतांत्रिक ढाँचे के संचालन और दिशा दोनों में व्यापक बदलाव किए हैं। वैश्वीकरण का प्रभाव केवल आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है; यह राजनीतिक मूल्यों, प्रशासनिक ढाँचों और नागरिक–राज्य संबंधों की प्रकृति को भी पुनर्परिभाषित करता है। भारत को अनेक नीतिगत निर्णय ऐसे लेने पड़े, जिनमें वैश्विक संस्थानों जैसे IMF, विश्व बैंक और WTO की सिफारिशों और घरेलू सामाजिक–आर्थिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाना पड़ा। इससे नीतिगत स्वायत्तता और बाहरी दबावों के बीच एक निरंतर तनाव विकसित हुआ। कई निर्णय विशेषज्ञ–चालित होते गए, जिससे संसद जैसे प्रतिनिधिक संस्थानों की deliberative भूमिका कुछ हद तक सीमित दिखाई देने लगी।

भारतीय लोकतांत्रिक संस्थाएँ भी इस प्रक्रिया से प्रभावित हुईं। संसद में आर्थिक सुधार, FDI नीति, पर्यावरणीय मानकों और व्यापार समझौतों जैसे विषयों पर कभी–कभी अपेक्षाकृत कम बहस देखी गई, क्योंकि इन क्षेत्रों में वैश्विक मानदंडों और बाजार–हितों को प्राथमिकता दी गई। न्यायपालिका ने भी वैश्विक मानवाधिकार, पर्यावरणीय मानकों और अंतरराष्ट्रीय कानूनों को कई मामलों में संदर्भ बिंदु बनाया, जिससे भारतीय न्याय–विमर्श में वैश्विक संवैधानिकता का प्रभाव बढ़ा।

चुनावी प्रणाली पर प्रभाव

चुनाव आयोग की भूमिका वैश्वीकरण के कारण और जटिल हुई है। डिजिटल युग में चुनाव प्रचार, विदेशी प्रभाव, बिग–डाटा और सोशल मीडिया की निगरानी एक नई चुनौती बनकर उभरी है। चुनावी वित्त पोषण में कॉरपोरेट पूँजी और बड़े उद्यमों का प्रभाव भी बढ़ा है, जिससे चुनाव आयोग को पारदर्शिता के नए मानक विकसित करने पड़े। इस प्रकार आयोग की भूमिका केवल निष्पक्ष चुनाव कराने तक नहीं, बल्कि डिजिटल सूचना की निगरानी तक विस्तृत हो गई।

लोक नीति निर्माण पर प्रभाव

वैश्वीकरण का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव नीति–निर्माण पर देखा जाता है। आर्थिक सुधार, निजीकरण, विनियमन–मुक्तिकरण, FDI उदारीकरण और वित्तीय बाजारों का विस्तार ये सभी भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के प्रयासों का हिस्सा हैं। इससे जहाँ विकास, निवेश, तकनीकी नवाचार और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है, वहीं सामाजिक सुरक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया। अतः लोकतांत्रिक नीति–निर्माण में बाज़ार–उन्मुख दृष्टिकोण अधिक प्रभावशाली हुआ।

राजनीतिक सहभागिता पर प्रभाव

डिजिटल क्रांति ने नागरिक सहभागिता में भी बड़ा बदलाव लाया। सोशल मीडिया ने राजनीतिक संवाद को लोकतांत्रिक बनाया, परंतु इसी माध्यम से misinformation, विदेशी हस्तक्षेप, hate campaigns और algorithmic bias जैसी चुनौतियाँ भी उभरीं। इससे राजनीतिक विमर्श की गुणवत्ता प्रभावित होती है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़े होते हैं।

केंद्र–राज्य सम्बन्ध पर प्रभाव

केंद्र–राज्य संबंध भी वैश्वीकरण से रूपांतरित हुए। 1991 के बाद राज्यों में FDI आकर्षित करने की प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जिससे Competitive Federalism मजबूत हुआ। कई राज्यों ने अंतरराष्ट्रीय निवेश सम्मेलनों और विदेशी साझेदारियों का विकास किया। GST के लागू होने से राज्यों की कराधान–स्वायत्तता कम हुई, परंतु राष्ट्रीय बाजार

अधिक समन्वित हुआ। इस कारण केंद्र–राज्य संबंध अब अधिक वित्तीय निर्भरता और प्रतिस्पर्धा वाले हो गए हैं।

चुनावी राजनीति पर प्रभाव

चुनावी राजनीति में वैश्वीकरण ने तकनीकी और प्रबंधन–आधारित मॉडल प्रस्तुत किया है। डिजिटल विज्ञापन, माइक्रो–टार्गेटिंग, बिग–डाटा विश्लेषण, इमेज–मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट फंडिंग चुनाव अभियानों की पहचान बन चुके हैं। इससे चुनाव पेशेवर हुए हैं, परंतु धन–प्रभाव और डाटा–नियंत्रण जैसी चुनौतियाँ भी बढ़ी हैं।

समाज और संस्कृति पर प्रभाव

सामाजिक–सांस्कृतिक स्तर पर वैश्वीकरण ने पहचान राजनीति, जीवनशैली और मूल्यों पर प्रभाव डाला है। वैश्विक मीडिया और उपभोक्ता संस्कृति ने युवाओं में नए मूल्य स्थापित किए, जबकि दूसरी ओर स्थानीय संस्कृति और भाषाओं पर दबाव बढ़ा। परिणामस्वरूप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और वैश्विक संस्कृति के बीच तनाव बढ़ने लगा।

विदेश नीति पर प्रभाव

विदेश नीति और सुरक्षा क्षेत्र में भी वैश्वीकरण निर्णायक कारक है। मल्टी–अलाइनमेंट, रक्षा सहयोग, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक व्यापार और आतंकवाद से निपटने की रणनीतियों में भारत अधिक सक्रिय और बहुआयामी बना है। डिजिटल खतरों और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं पर निर्भरता ने सुरक्षा नीतियों को नई दिशा दी है।

हालाँकि वैश्वीकरण कई अवसर प्रदान करता है, परंतु इससे असमानता, बेरोजगारी, सांस्कृतिक तनाव, पर्यावरणीय दबाव और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व कमजोर पड़ने जैसी चुनौतियाँ भी उत्पन्न होती हैंभविष्य की दिशा एक संतुलित मॉडल में है जहाँ आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय, वैश्विक सहभागिता, तकनीकी नवाचार और लोकतांत्रिक पारदर्शिता एक साथ आगे बढ़ें।

निष्कर्ष

वैश्वीकरण भारत के लिए न तो पूर्ण लाभ का माध्यम रहा है और न ही पूर्ण हानि का कारण। इसके प्रभाव बहुआयामी, जटिल और निरंतर परिवर्तनशील हैं। पिछले तीन दशकों में भारत ने वैश्वीकरण के माध्यम से आर्थिक उदारीकरण, तकनीकी प्रगति, वैश्विक नेटवर्किंग, निवेश वृद्धि और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं परंतु इसी प्रक्रिया ने कई चुनौतियाँ भी उत्पन्न की जैसे आय असमानता, रोजगार संरचना में परिवर्तन, सांस्कृतिक द्वंद्व, नीतिगत निर्भरता और साइबर–खतरों का विस्तार। भारत के राजनीतिक ढांचे पर वैश्वीकरण का प्रभाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा है। लोकतांत्रिक संस्थाओं, चुनावी राजनीति, सार्वजनिक नीति, मीडिया, नागरिक भागीदारी और केंद्र राज्य संबंधों में व्यापक परिवर्तन दिखाई देते हैं। वैश्वीकरण ने राजनीतिक संचार को अधिक तकनीकी, फंडिंग को अधिक कॉरपोरेट–केंद्रित, और नीति–निर्माण को अधिक विशेषज्ञ–आधारित बना दिया है। इससे लोकतंत्र में दक्षता तो बढ़ी है, परंतु पारदर्शिता और सहभागिता पर नए प्रकार के प्रश्न भी उठे हैं।

भारत की सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना में भी वैश्वीकरण ने गहरा प्रभाव डालाकृजहाँ एक ओर विविधता, आधुनिक जीवनशैली और वैश्विक संवाद ने समाज को अधिक उदार और गतिशील बनाया, वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक पहचान, परंपरागत मूल्यों और स्थानीय उद्योगों पर दबाव बढ़ा। इस दोहरी प्रक्रिया ने भारत में सांस्कृतिक मिश्रण (hybrid culture) के नए रूपों को जन्म दिया, पर राजनीति में पहचान संघर्षों को भी तीव्र किया। सुरक्षा और विदेश नीति के क्षेत्र में वैश्वीकरण ने भारत को एक नए वैश्विक ढाँचे का महत्वपूर्ण भागीदार बनाया। ऊर्जा सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, रक्षा सहयोग, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में भूमिका, और इंडो–पैसिफिक रणनीति ने भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत किया। भारत अब केवल "उभरती अर्थव्यवस्था" नहीं, बल्कि "निर्णायक वैश्विक शक्ति" बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालाँकि, इन उपलब्धियों के बावजूद चुनौतियों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वैश्विक अर्थव्यवस्था की अनिश्चितता, तकनीकी असमानता, डिजिटल निगरानी, साइबर सुरक्षा, जलवायु संकट और भू–राजनीतिक तनाव ये सभी ऐसे मुद्दे हैं जिनसे भारत को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टि से निपटना होगा। समग्र रूप से कहा जाए तो वैश्वीकरण भारत के लिए अवसर भी है और परीक्षा भी। यह किसी एक दिशा में ले

जाने वाली प्रक्रिया नहीं, बल्कि निरंतर बदलता हुआ वैश्विक परिवेश है जिसमें भारत को अपनी विशिष्ट पहचान, लोकतांत्रिक मूल्यों और विकास लक्ष्यों को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ना है।

निष्कर्षतः, भारत को ऐसी नीतियाँ, राजनीतिक संरचनाएँ और सामाजिक रणनीतियाँ विकसित करनी होंगी जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए घरेलू समावेशिता और राष्ट्रीय स्वायत्तता को भी समान रूप से महत्व दें। भविष्य का भारत वही होगा जो वैश्विक अवसरों को आत्मनिर्भरता, नवाचार और सामाजिक न्याय के साथ जोड़ सके।

संदर्भ सूची

1. Amin, S. (1997) *Capitalism in the Age of Globalization: The Management of Contemporary Society,* Zed Books, London.
2. Bhagwati, J. (2004) *In Defense of Globalization,* Oxford University Press, Oxford.
3. Castells, M. (1996) *The Rise of the Network Society,* Blackwell Publishing, Oxford.
4. Giddens, A. (1990) *The Consequences of Modernity,* Polity Press, Cambridge.
5. Held, D. & McGrew, A. (2007) *Globalization/Anti-Globalization: Beyond the Great Divide,* Polity Press, Cambridge.
6. Nayar, B. R. (2001) Globalization and Nationalism: The Changing Balance in India's Economic Policy, 1950–2000, Sage Publications, New Delhi.
7. Sen, A. (1999) *Development as Freedom,* Oxford University Press, Oxford..
8. शर्मा, अ. (2010) *वैश्वीकरण और भारतीय राजनीति,* राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
9. वर्मा, र. (2012) *भारतीय समाज और वैश्वीकरण,* विद्या प्रकाशन, दिल्ली।
10. सिंह, पी. (2008) *आर्थिक सुधार और नीति निर्माण में वैश्वीकरण,* हरिवंश प्रकाशन, लखनऊ।
11. कुमार, ए. (2015) *वैश्वीकरण और चुनावी राजनीति,* प्रभात प्रकाशन, जयपुर।
12. दत्ता, एन. (2009) *सामाजिक नीतियों और वैश्वीकरण,* लोकसाहित्य प्रकाशन, पटना।

****